

अक्षरधाम मंदिर के पास बना है अवैध पिकअप प्वाइंट, बस चालकों के आगे बेबस पुलिस

सुषमा रानी

दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर के नजदीक अवैध पिकअप प्वाइंट बनने के कारण दिल्ली पुलिस के लिए कड़ी चुनौती है। रात के वक्त यात्री फ्लाईओवर व सड़कों पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं। इसी का फायदा उठाकर बदमाश उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। बस चालकों के आगे पुलिस बेबस नजर आती है। त्योहारी सीजन को देखते यहां पर फिलहाल भीड़ देखी जाती है।

पूर्वी दिल्ली। अक्षरधाम मंदिर के आसपास डगगामार बस चालक और ट्रेवल एजेंसियों ने अवैध रूप से पिकअप प्वाइंट बनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) एक साल से यह प्वाइंट खत्म करने में लगी हुई है, लेकिन बस चालकों की मनमानी के आगे दिल्ली पुलिस बेबस नजर आती है। पिछले साल दिवाली (Diwali 2024) के



(Delhi Police) एक साल से यह प्वाइंट खत्म करने में लगी हुई है, लेकिन बस चालकों की मनमानी



के आगे दिल्ली पुलिस बेबस नजर आती है। पिछले साल दिवाली (Diwali 2024) के

मौके पर मंडावली थाना ने प्वाइंट को खत्म करने के लिए मंदिर के पास सड़क पर समानंतर बैरिकेड लगाए गए थे। यह बैरिकेड अभी भी लगे हैं, लेकिन यह जिस उद्देश्य के लिए लगाए गए थे वह पूरा नहीं हो रहा है।

दिवाली में चंद दिन रह गए हैं। ऐसे में लोग दिल्ली से दूसरे राज्य अपने घर जा रहे हैं। अक्षरधाम फ्लाईओवर व इसके आसपास की सड़कों पर रात में जगह-जगह यात्रियों को जमावड़ा देखने को मिल रहा है। साइकिल पर लोग खाने पीने का सामान बेच रहे हैं।

दिन की बजाय रात में दिखती है बसों फ्लाईओवर को डगगामार बस चालकों ने मुख्य प्वाइंट बनाया हुआ था, लेकिन अब पांडव नगर एनएच-नौ का नया प्वाइंट बना लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि दिन में यहां बसें नजर नहीं आती हैं, लेकिन शाम होते ही सड़कों व फ्लाईओवर पर बिहार, प्रयागराज, मध्य प्रदेश समेत कई जगह के लिए बसे यात्रियों के लिए आकर खड़ी हो जाती हैं।

पुलिस सख्ती कर रही है तो अक्षरधाम फ्लाईओवर (Akshardham flyover) से आगे जाकर मयूर विहार में सड़क किनारे खड़े होकर यात्री बसों का इंतजार कर रहे हैं। आरोप है ट्रांसपोर्ट विभाग, पुलिस, प्रशासन के कई अधिकारियों को मिलीभगत के कारण अवैध प्वाइंट पर लगाम नहीं लगा पा रही है।

बसों के ऐप पर पिकअप प्वाइंट है अक्षरधाम रेड बस समेत कई ट्रेवल एजेंसियों के मोबाइल

ऐप पर अक्षरधाम पिकअप प्वाइंट है। रात के वक्त यात्री बसों का इंतजार करते हैं। सड़क सुनसान होने की वजह बदमाश उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। आरोप है कि ट्रेवल एजेंसी वाले मेट्रो के पिलर नंबर 36 के पास उन्हें बुलाते हैं।

जब वह वहां आकर खड़े हो जाते हैं तो फोन करके उनसे कहते हैं यहां बस नहीं रुकेगी फ्लाईओवर पार करके मयूर विहार आ जाओ। ऐसे में यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। महिला यात्रियों के लिए भी यह अवैध प्वाइंट खतरनाक है।

मैंने कुछ ही दिन पहले कार्यभार संभाला है। मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। वहां अगर इस तरह की समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा।

राजीव रावल, जिला पुलिस उपायुक्त पूर्वी रेंज।

दिल्ली में हाईटेंशन पोल पर चढ़ा शख्स, PM मोदी, सीएम और चीफ जस्टिस से बातचीत कराने की करने लगा जिद्द

दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना खादर क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति एक हाई-वोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ गया है। उसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हाईटेंशन पोल पर चढ़ा व्यक्ति पीएम नरेंद्र मोदी सीएम आतिशी और मुख्य न्यायाधीश से बातचीत की मांग करने लगा।



और प्रधानमंत्री से बात करने पर अड़ा था।

अधिकारी मीना ने बातचीत में कहा “सुबह 10:30 बजे, हमें एक व्यक्ति के बारे में फोन आया जो हाई-टेंशन तार के खंभे पर चढ़ गया था। वह पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश से बात करने की मांग कर रहा था। यह स्पष्ट नहीं है कि कहाँ है वह वहाँ से हैं, क्योंकि वह विरोधभासी जानकारी दे रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने बंगाल या बिहार से होने का उल्लेख किया और शिक्षक के

रूप में काम करने का दावा किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) स्थित अरावली हॉस्टल (Aravali Hostel) में मंगलवार देर रात एमएससी द्वितीय वर्ष के छात्र ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट वरामद नहीं मिला। छात्र के कमरे से मिले मेडिकल रिपोर्ट से उसके मनोरोग से ग्रसित होने की बात कही गई।

पुलिस उसके दोस्तों के बयान दर्ज मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद झारखंड में परिवार को सूचित किया गया। पुलिस ने घटना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि देर रात आईआईटी दिल्ली के एक हॉस्टल में छात्र के खुदकुशी की सूचना मिली। इस पर पुलिस कमरा नंबर डी-57 पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। स्टाफ व छात्रों ने खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर प्रवेश किया।

जानलेवा प्रदूषण की जिम्मेदारी लेते आतिशी तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे- देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी राजधानी में दमघोड़ प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बजाय आरोप प्रत्यारोप की बयानबाजी करके वायु प्रदूषण के लिए सरकारी तंत्र को पूरी तरह असहाय बना रही हैं और प्रदूषित जल के लिए मुख्यमंत्री कह रही है कि वजीराबाद बैराज में आने वाले पानी में अमोनिया का स्तर अधिक है कि उसे ट्रीट नही किया जा सकता। यादव ने कहा कि यह चिंताजनक है कि आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के बावजूद वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में असमर्थता दिखाना उनकी नाकामी को दर्शाता है, उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

आज जहांगीरपुरी में अत्यंत खतरनाक 417 एक्यूआई दर्ज हुआ, जबकि वजीरपुर में 392, द्वारका सेक्टर 8 में 308, मुंडका में 373, रोहिणी में 388, एनएसआईटी द्वारका में 398 एक्यूआई दर्ज किया गया और मुख्यमंत्री और प्रदूषण मंत्री कह रहे हैं कि हम प्रदूषण नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

यादव ने कहा कि क्यों मुख्यमंत्री आतिशी और इनक मंत्रीमंडल हरियाणा और यूपी में पराली जलाने और यमुना में औद्योगिक कचरा बिना ट्रीट किए छोड़ने की बात करते हैं परंतु पंजाब में पराली जलाने और दिल्ली के नालों का



बिना ट्रीट किए गंदा पानी सीधा यमुना में गिर रहा है, जिसके लिए दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर जिम्मेदार है, उस पर पूरी तरह चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि आतिशी को बयान देते हुए यह समझना चाहिए कि वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उन्हें औखी भाषा और आरोप प्रत्यारोप करने की जगह अपने पद की संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करके दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए काम करें।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोगों का विश्वास खो चुकी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की मुख्यंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री

अरविन्द केजरीवाल ने पिछले 11वर्षों में प्रदूषण जैसी प्रमुख समस्या के अफफल प्रयास करने के अलावा कुछ नहीं किया। श्री यादव ने कहा कि आतिशी कह रही है कि हम पानी के स्पे, एंटी-स्मॉग गन के जरिए प्रदूषण नियंत्रण का समाधान कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 1,47,488 हैक्टर क्षेत्रफल की दिल्ली का प्रदूषण पानी के स्पे, एंटी स्मॉग गन या रेड लाईट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसे नाकाम प्रयासों से प्रदूषण नियंत्रित हो सकता है ?

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडल सभी दमघोड़ प्रदूषण को नियंत्रित करने की बजाय

दिल्ली वालों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जब आई.ए.आर.आई के आंकड़े साफ दर्शा रहे हैं कि पंजाब में पराली जलाने के 1581 मामले हुए हैं, हरियाणा में 665 और उत्तर प्रदेश में 740 घटनाएं हुईं फिर अरविन्द केजरीवाल, आतिशी, गोपाल राय सहित आप नेता क्यों पंजाब के राजनीति हित में संरक्षण कर रहे हैं जबकि आंकड़ों के अनुसार पंजाब ने उत्तर भारत को पराली प्रदूषण की आग में झोंकने का बड़ा दोषी है, जिसके प्रति सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि पिछले वर्ष 2023 में पंजाब में लगभग 9000 घटनाएं पराली जलाने की सामने आई थी।

'बंदा सिंह चौधरी' फिल्म की स्टारकास्ट ने किया स्पर्श ग्लोबल स्कूल का दौरा

सुषमा रानी

हाल ही में, एक्टर अरशद वारसी, मैहर विज और अभिनेता अरबाज खान अपनी आनेवाली फिल्म 'बंदा सिंह चौधरी' के प्रचार के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे। उनके साथ निर्देशक अभिषेक सक्सेना और फिल्म के सह-निर्माता मनोष भी प्रमोशनल कार्यक्रम में उपस्थित थे। उनका प्रचार नई दिल्ली के स्पर्श ग्लोबल स्कूल में जश्न-ए-काफिला में आयोजित किया गया। फिल्म 'बंदा सिंह चौधरी' 25 अक्टूबर, 2024 को रिलीज होगी।

फिल्म 'बंदा सिंह चौधरी' वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद पंजाब में सांप्रदायिक दंगों के दौरान की कहानी पेश करती है। इसमें यह दिखाया गया कि एक आदमी किस तरह देश विभाजन और भयंकर हिंसा के बीच अपने अधिकारों के लिए परिवार के अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। एक साधारण आदमी अपने परिवार के अधिकारों की रक्षा करने, विभाजन की गहरी पीड़ा और हिंसा के बीच खुद को जीवित रखने के लिए लड़ता और जुझता है। अभिनेता अरशद वारसी ने बताया, 'मुझे आज इस फिल्म के प्रमोशनल कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हो रही है।' उन्होंने कहा कि आप जो भी लोग फिल्म निर्माता—निर्देशक या लेखक बनने की खाहिश रखते हैं, तो इसे मूर्त रूप दें। मैं तो मानता हूं कि लेखन एक बेहद खूबसूरत काम है, इसलिए कृपया इसे जारी रखें।'



महिलाओं को 1000 रुपये देने का वायदा तो पूरा किया नही, अब नई योजना चुनावी स्टंट है।- देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि 3-4 चार महीने में दिल्ली सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और पिछले 11 वर्षों में दिल्ली की जनता विशेषकर वृद्ध, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं की की पूरी तरह अनदेखी करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार हर दिन नई घोषणा करके दिल्लीवालों को फिर एक अपने भ्रमर जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश है। 60 प्रतिशत दिव्यांगों को 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा केवल खोखली बयानबाजी है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों अपनी खिसकी हुई जमीन को स्थिर करना चाहती है।

यादव ने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि जब वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पिछले कई वर्षों से पेंशन नहीं मिलने के कारण



केन्द्र सरकार को कोसते हैं फिर नई योजना के लिए पैसा कहाँ से आने वाला है जबकि पिछले कई वर्षों में कोई नई पेंशन योजना शुरू नहीं की, फिर दिल्ली सरकार चुनाव नजदीक आते ही 60 प्रतिशत दिव्यांगों को 5000 रुपये पेंशन की घोषणा करके कहना कि जल्द पंजीकरण करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्टी दिव्यांगों को भी धोखा दे रही है।

उन्होंने कहा कि 5000 रुपये दिव्यांगजनों को पेंशन भी आप सरकार का एक और खोखला वादा साबित होगा जैसे 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से अधिक की प्रत्येक महिला को

1,000 रुपये प्रति माह का सम्मान देने का प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं लेने के बाद जमना साबित हुआ। उन्होंने कहा कि फिर दिल्ली की निष्क्रियता के कारण लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग अपनी पेंशन के लिए सरकार के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। पिछले महीने में आ गया हूँ सबको पेंशन मिलेगी, सब गुमराह करने वाली बातें हैं, केजरीवाल दिल्ली वालों को चोतरफा गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच चला आदमी पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का मान बना चुकी है।

नेहा धूपिया ने दिल्ली में लाइमलाइट डायमंड्स के एक्सक्लूसिव स्टोर का उद्घाटन किया

सुषमा रानी

भारत के सबसे बड़े लैब ग्रेन डायमंड ब्रांड, लाइमलाइट डायमंड्स ने भारत की राजधानी दिल्ली में अपने दूसरे एक्सक्लूसिव स्टोर का शुभारंभ किया। दिल्ली के प्रतिष्ठित राजौरी गार्डन इलाके में इस विशेष लैब ग्रेन डायमंड ज्वेलरी की मांग को पूरा करने के लिए यह स्टोर खोला है। नए स्टोर का उद्घाटन प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया, लाइमलाइट डायमंड्स के को-फाउंडर नीरव भट्ट के साथ लाइमलाइट डायमंड्स के डायरेक्टर करम चावला सहित कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां इसमें शामिल हुईं।

1500+ स्वकार्य फ्री में भव्य रूप से फैला यह स्टोर लाइमलाइट डायमंड्स के लिए एक और माइलस्टोन है, जिससे वे पूरे भारत में अपना विस्तार जारी रख रहे हैं। पिछले दो वर्षों में, ब्रांड ने तेजी से विकास की गति को देखा है। अब तक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद, राजकोट, बैंगलोर, चेन्नई आदि सहित 35 से अधिक शहरों में मौजूदगी के साथ एलजीडी ज्वेलरी के लिए देश में इस ब्रांड ने तेजी से खुद को अल्टीमेट सॉल्यूशन डिस्टिनेशन के



रूप में स्थापित किया है।

ब्रांड के एक्सक्लूसिव कलेक्शन को निहारते हुए अभिनेत्री नेहा धूपिया ने कहा, 'मैं इस स्टोर के लैब ग्रेन डायमंड ज्वेलरी के कलेक्शन से काफी आकर्षित हूँ, वे भारत में बने हैं और मुझे लगता है कि हर भारतीय महिला इन डायमंड्स को पहनने में गर्व महसूस करेगी।'

मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि सोने चांदी तो आप हमेशा खरीदने हो और खरीदने के बाद आपको लगता है कि बहुत पैसा खर्च हो गया अगले बार कुछ नहीं खरीदूंगा लेकिन इस धनतेस पर आप *लाइमलाइट* से डायमंड ज्वेलरी खरीद सकते हो जो ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा और आपके बजट में आ जाएगा

लाइमलाइट डायमंड्स की

फाउंडर और एमडी पूजा शेट माधवन ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, 'दिल्ली में लाइमलाइट के पहले आउटलेट में हमारे कलेक्शन और डिजाइन को लेकर ग्राहकों से शानदार रिसॉन्स मिलने के बाद हम दिल्ली में अपना दूसरा स्टोर खोलने के लिए बेहद उत्साहित हैं।' इस शहर को चमक-दमक हमारे ब्रांड को बड़े अच्छे से कॉम्युनिटी करते हैं।

यहां उन सभी लोगों के लिए एक बेहतर नजर कलेक्शन है, जो स्मॉल डायमंड ज्वेलरी से सॉल्यूशन ज्वेलरी की ओर जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा, हमारे ब्रांड द्वारा दिये जाने वाले बायबैक और एक्सचेंज ऑफर यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्रांडेड उत्पाद का मूल्य पूरी तरह से सुरक्षित है, ताकि वे अपनी चमक का आनंद ले सकें।

15 गांव के लोगों के लिए नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला, आबादी का सर्वे पूरा; अब बनेगी पेरिफेरल रोड

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा में रहने वाले 15 गांव के लोगों के लिए राहत वाली खबर है। आबादी विवाद के समाधान का रास्ता निकाल लिया गया है। अब यहां पर पेरिफेरल रोड बनाई जाएगी। बता दें मास्टर प्लान में शामिल सभी गांवों में आबादी सर्वे होगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के खिलाफ आबादी अधिग्रहण के हजारों मामले विचाराधीन हैं।

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने आबादी विवाद के समाधान का रास्ता तैयार कर दिया है। गांवों में विस्तारित आबादी को छोड़कर पेरिफेरल रोड बनाई जाएगी। प्राधिकरण क्षेत्र के 15 गांवों की आबादी का सर्वे पूरा कर लिया गया है।

प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में सर्वे रिपोर्ट रखी जाएगी। इसके साथ ही पेरिफेरल रोड बनाने की अनुमति ली जाएगी। मास्टर प्लान में शामिल सभी गांवों की आबादी का सर्वे कराया जाएगा।

औद्योगिक विकास के लिए प्राधिकरण किसानों की जमीन का अधिग्रहण करते हैं, लेकिन खेती की जमीन के साथ आबादी के अधिग्रहण का आरोप लगाकर किसान प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के खिलाफ आबादी अधिग्रहण के हजारों मामले विचाराधीन चल रहे हैं। किसान संगठन प्राधिकरणों के खिलाफ धरना प्रदर्शन से लेकर



जमीन पर कब्जा देने को तैयार नहीं है। जमीन न मिलने से प्राधिकरणों की परियोजनाएं अटक ही हुई हैं।

आबादी संबंधित मामलों के समाधान के लिए यमुना प्राधिकरण ने नई रणनीति तैयार की थी। इसे अमलीजामा पहनाना शुरू हो चुका है। इसके तहत गांवों का ड्रोन सर्वे कराया गया है। इसमें गांवों की

मूल आबादी के साथ विस्तारित आबादी को भी शामिल किया गया है।

आबादी भूखंड विकसित कर किसानों को किया जाएगा आवंटित

इस सर्वे के आधार पर गांव के चारों ओर पेरिफेरल रोड का निर्माण होगा। आबादी की ओर की जमीन पर जिन किसानों का कब्जा है, उन्हीं के



की स्वीकृति लेकर पेरिफेरल रोड का निर्माण होगा। सर्वे और पेरिफेरल रोड के निर्माण से आबादी अधिग्रहण को लेकर होने वाले विवादों की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी।

इन्हें अधिग्रहण प्रस्ताव से रखा जाएगा बाहर

सर्वे के आधार पर ही तैयार होंगे जमीन

अधिग्रहण के प्रस्ताव यमुना प्राधिकरण गांवों में जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव आबादी सर्वे के आधार पर ही तैयार करेगा। जिन खसरा नंबर में आबादी होगी, उन्हें अधिग्रहण प्रस्ताव से बाहर रखा जाएगा। प्राधिकरण ने सर्वे के लिए पूर्व में जिला प्रशासन को भेज गए अधिग्रहण प्रस्ताव भी वापस मंगा लिए थे।

गुरुग्राम में GMDA की अतिक्रमण पर हुई बड़ी कार्रवाई, एमजी रोड और सोहना रोड पर चला बुलडोजर

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने एमजी रोड सोहना रोड फाजिलपुर रोड और घसोला रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। इस अभियान में अवैध निर्माण ठेले रेहड़ी और ढाबों के अवैध बैठने के क्षेत्रों को हटाया गया। जीएमडीए ने प्रमुख सड़कों और ग्रीनबेल्ट को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। जीएमडीए ने विक्रेताओं से प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के निर्देश दिए।



जीएमडीए द्वारा चलाए जा रहे नियमित अतिक्रमण विरोधी अभियान में जीएमडीए की प्रमुख सड़कों और ग्रीनबेल्ट को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई

डीटीपी, जीएमडीए, आरएस बाट के नेतृत्व में यह अभियान एमजी रोड से शुरू हुआ, जो तीन घंटे तक चला। इस दौरान अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की गई। गुरुग्राम नगर निगम की टीम ने इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग किया और एमजी रोड से 27 अवैध गाड़ियां हटाई गईं। इस अभियान में जीएमडीए टीम के साथ ट्रैफिक पुलिस भी शामिल थी और उन्होंने गलत पार्किंग के करीब 62 चालान जारी किए और साथ ही ट्रैफिक जाम का कारण बन रही आठ

कारों को जब्त किया गया।

टीम ने सोहना रोड पर सार्वजनिक स्थानों पर ढाबा संचालकों द्वारा बनाए गए अवैध बैठने के क्षेत्रों को और रेहड़ी वालों द्वारा अतिक्रमण करने वालों को हटाया। उन्होंने सभी विक्रेताओं से अनुरोध किया कि वे क्षेत्र को खाली कर दें, अन्यथा सड़क किनारे लगे ठेले डीटीपी इंफोसमेंट द्वारा हटा दिए जाएंगे। अभियान के दौरान मौजूद लोगों ने डीटीपी को सोहना रोड पर अन्य प्रमुख बिंदुओं के अलावा फाजिलपुर रोड और घासोला रोड के प्रवेश बिंदुओं का निरीक्षण करने का अनुरोध भी किया।

पॉलीथिन के उपयोग पर होगी कार्रवाई

डीटीपी ने विक्रेताओं द्वारा लगाए गए ठेलों का भी निरीक्षण किया और यह पाया कि वे भारी मात्रा में पालीथिन का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने इन सभी को प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और प्लास्टिक मुक्त गुरुग्राम शहर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान सेक्टर 49 में घसोला रोड, सेक्टर 48 में सोहना रोड से फाजिलपुर रोड तक अतिक्रमण करने वाले 15 खोखे और पांच विक्रेताओं को भी हटा दिया गया।

जमकर गरजा GDA का बुलडोजर, कई अवैध कॉलोनियां ध्वस्त; पांच होटलों पर भी हुआ एक्शन

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ जीडीए की कार्रवाई जारी है। ताजा मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने हरनंदी डूब क्षेत्र में अवैध रूप से काटी जा रही पांच कॉलोनियों में बुलडोजर चलाया। अवैध प्लॉटिंग करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही आवास विकास परिषद ने 53 डिफाल्टरों के खिलाफ आरसी जारी की है।

साहिबाबाद। हरनंदी डूब क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग कर काटी जा रही पांच कॉलोनियों में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की टीम ने मंगलवार को बुलडोजर चलाया। कॉलोनी की चारदीवारी, सड़क आदि को ध्वस्त कर दिया। अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इन इलाकों में काटी जा रही थी कॉलोनियां

प्रवर्तन जोन आठ के करहैड़ा, असातपुर, हरनंदी, सिकरानी, चिरोडी रोड, प्रेम नगर, रामेश्वर पार्क, गढ़ी कटेया गांव में डूब क्षेत्र में पांच अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉटिंग की जा रही थी। कॉलोनी में प्लॉट बेचे जा रहे थे। प्लॉट बेचने के लिए उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा था। अनजाने में लोग प्लाट खरीदकर अपनी जमा पूंजी को निवेश कर रहे थे।

शिकायत मिलने पर जीडीए की टीम कॉलोनी में पहुंची। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त



कर दिया गया। कार्रवाई के समय सहायक अभियंता, अवर अभियंता और सुरवाइजर स्टाफ के साथ उपस्थित रहे। निर्माणकर्ता को निर्देशित किया गया है कि वह मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण करें।

डिफाल्टरों को आरसी जारी

आवास विकास परिषद ने 53 डिफाल्टरों के खिलाफ आरसी जारी की है। सभी पर करीब पांच करोड़ रुपये का बकाया है। इनके खिलाफ तहसील स्तर से नोटिस, कुर्की और गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है।

आवास विकास परिषद के संपत्ति प्रबंधक नृपेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि डिफाल्टरों पर करीब 10 वर्ष से बकाया है। नोटिस जारी करने के बाद भी डिफाल्टरों ने बकाया जमा नहीं किया। इससे विभाग को आर्थिक क्षति हो रही है।

बजरिया के पांचों होटल सील

सितंबर माह में देह व्यापार का मामला सामने आने के बाद बजरिया के पांच होटल जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सील कर दिए हैं। दैनिक जागरण ने चार अक्टूबर के अंक में बिना लाइसेंस चल रहे थे। 'बजरिया के पांच होटल, होंगे सील' शीर्षक के साथ समाचार प्रकाशित कर बताया था कि जिला प्रशासन ने होटल सील करने की संसृति कर दी है।

होटल मालिक युवतियों से कराते थे देह व्यापार

26 सितंबर को एसीपी कोतवाली रितेश

त्रिपाठी ने बजरिया के पांच होटल में पुलिस टीम के साथ छापा मार था। इस दौरान होटल में देह व्यापार का पर्दाफाश हुआ था। पुलिस ने युवतियों को रेस्क्यू किया तो पता चला कि होटलों में नौकरी के बहाने युवतियों को बुलाकर होटल मालिक देह व्यापार कराते थे।

इस मामले में कोतवाली पुलिस ने होटल के लाइसेंस की जानकारी जिला प्रशासन से मांगी थी। जिला प्रशासन ने जब होटल संचालकों को सराय एक्ट के तहत लाइसेंस लेने के संबंध में नोटिस जारी कर जानकारी मांगी तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद जिला प्रशासन ने होटलों को सील करने के लिए पत्र जारी कर दिया था।

बदलते वक्त की मांग है हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के बारे में सोचना

कमलेश पांडे

ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है, फिर दूसरी बड़ी आबादी इस्लाम मतावलंबियों की है। जबकि हिन्दू आबादी संसार की तीसरी बड़ी आबादी है। व्यापार में भी इसी तरह से संख्या बल में हिंदू कारोबारी तीसरे पायदान पर हैं।

राष्ट्रीय राजनीति की अपनी चिंताएं हैं, जबकि सुबाई राजनीति की अपनी दुश्चिंताएं। लोकतांत्रिक सियासत में इनमें तालमेल बिठाना वाकई दुष्कर कार्य है, क्योंकि राष्ट्रीय हितों के ऊपर कहीं साम्प्रदायिक, कहीं जातीय और कहीं क्षेत्रीय हितों को हावी किया जाता रहा है और ऊटपटांग वकालत की जाती रही है। ऐसे में हरेक सिक्के के दो पहलु की तरह ही इन्हें भी लिए जाने की जरूरत है और हमारे समग्र राष्ट्रीय हित कैसे सध सके, इसके लिए प्रार्थमिकता तय किये जाने की जरूरत है।

देखा जाए तो भारत में अप्रत्याशित रूप से मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या जहां कुछ राजनीतिक दलों व सामाजिक संस्थाओं के लिए चिंता की बात है और इन्हें नियंत्रित किये जाने की वकालत हिन्दू समुदाय के नेता व समाजसेवी खुलेआम कर रहे हैं और तत्सम्बन्धी डेटा भी सार्वजनिक कर रहे हैं। वहीं, इस बात की वकालत भी की जा रही है कि हिंदुओं को भी बंध्याकरण व नस्लबंदी की नीति का परित्याग करके ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, ताकि मुस्लिमों के मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा बनी रहे। कमोबेश यही वैश्विक डिमांड भी है। हमारे पास अकूत प्राकृतिक संसाधन हैं, पास-पड़ोस में जनसंख्या के समुचित समायोजन की संभावनाएं हैं और शेष विषय में बहुत सारे भूभाग आबादी विहीन हैं, जहां रणनीतिक रूप से हिंदुओं को बसाने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे वीर-बांकुडों और समझदार लोगों की मांग यत्न-तत्न-सर्वत्र है। हां, इसके लिए स्पष्ट वैश्विक, राष्ट्रीय और सुबाई सोच होनी चाहिए और सबमें बेहतर तालमेल की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए।



ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है, फिर दूसरी बड़ी आबादी इस्लाम मतावलंबियों की है। जबकि हिन्दू आबादी संसार की तीसरी बड़ी आबादी है। व्यापार में भी इसी तरह से संख्या बल में हिंदू कारोबारी तीसरे पायदान पर हैं। यही वजह है कि हिंदुओं को भी अपनी आबादी मुस्लिमों की तरह बेतहाशा बढ़ानी चाहिए और ईसाई व इस्लाम मतावलंबियों की तरह वैश्विक मतांतरण अभियान दुनिया के हरेक देशों में छेड़ना चाहिए। चूंकि अधिकांश धर्म सनातन मतावलंबियों से ही टूटकर बने हैं, इसलिए घरवापसी अभियान भी चलाया जा सकता है। इसके लिए हिन्दू धर्म को सरल बनाना होगा, ताकि अल्प आय वर्ग के लोग भी इसमें फिट बैठ सकें और मौजूदा आडंबरों की मार उनपर नहीं पड़े। कहना न होगा कि यदि ऐसी रणनीति नहीं अपनाई गई तो निकट भविष्य में अस्तित्व रक्षा के भी लाले पड़ जाएंगे।

इतिहास साक्षी है कि ईसाई व यहूदी धर्म की उत्पत्ति भी इस्लाम धर्म से ही हुई है, इसलिए जब दोनों जुड़वां धार्मिक ताकतें एक हो जाएंगी तो हिंदुओं की वैश्विक परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि का विचार दूरदर्शिता भरा दृष्टिकोण है, यदि सही मायने में देखा जाए तो। इसलिए अब जो दक्षिण भारत से जनसंख्या वृद्धि के

सिरे से परिसीमन होना है। इस परिसीमन के मुताबिक दस लाख लोगों की आबादी पर एक सांसद होगा।

चूंकि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के मामले में तो बेहतरीन प्रदर्शन कर किया है, जिसकी वजह से वहां प्रजनन दर कम हो गयी है। इसलिए उन्हें अब यह डर सता रहा है कि यदि आबादी के लिहाज से संसदीय सीटों का निर्धारण हुआ तो देश की राष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह उत्तर भारत केन्द्रित हो जायेगी। लेकिन यदि हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के नजरिए से देखा जाए तो दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों का ताजा आह्वान भारत और हिंदुत्व दोनों के लिए बरदान साबित हो सकता है। इसलिए यह कहना कि देश में एक ओर उत्तर भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाये जाने की मांग हो रही है तो दूसरी ओर दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं, में कोई दिक्कत नहीं है। बस, उत्तर भारत के नेताओं को अपना नजरिया बदलना होगा और हिंदुओं की जनसंख्या में अधिकाधिक वृद्धि की रणनीति बनानी होगी। वहीं, मोदी सरकार को भी बदलते नजरिए के मुताबिक विदेश नीति बनानी होगी।

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) द्वारा तैयार इंडिया एंजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में बुजुर्गों की आबादी अधिक है। इसे संतुलित करने के लिए ही टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछले हफ्ते कहा था कि लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए कानून लाने की योजना भी बना रही है। राज्य की बुजुर्ग होती आबादी को देखते हुए यह एक नैक कदम है।

इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक पुराने आशीर्वाद का जिक्र करते हुए लोगों को 16 बच्चे पैदा करने की सलाह और शुभकामना दे डाली। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र में फ्लोटिंग हाउस बनाने और ऐसे ही प्राकृतिक जमीन विकसित करने की पूरी गुंजाइश है। बहरहाल, दोनों मुख्यमंत्री यह सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जल्द ही देश में संसदीय सीटों का नये

17.1% हो जाएगी।

इसप्रकार मोटे तौर पर यदि देखें तो 15 साल की इस अवधि में जनसंख्या में बुजुर्गों का अनुपात दक्षिण में 6-7% बढ़ जाएगा जबकि उत्तर में यह लगभग 3-4% होगा। वैसे एक बात गौर करने लायक है कि अधिकांश दक्षिण भारतीय राज्य दुनिया के विकसित देशों की प्रजनन स्तर तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 2016-19 के लिए एकत्र किए गए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में जीवन प्रत्याशा 69.1 वर्ष, केरल में 71.9 वर्ष और तमिलनाडु में 71.4 वर्ष थी। केवल कर्नाटक की जीवन प्रत्याशा दर राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम यानि 67.9 थी।

वहीं, एक समस्या यह है कि भारत ने अपनी प्रजनन दर बहुत तेजी से कम की है। जहां प्रति महिला छह बच्चों से घटकर दो या एक बच्चे पर आने में फ्रांस को 285 साल लगे, इंग्लैंड को 225 साल लगे, किंतु भारत को इस काम में महज 45 साल लगे। हालांकि, चीन ने इससे भी कम समय में जनसंख्या को नियंत्रित किया, लेकिन वहां ऐसा अत्यंत कठोर और दंडात्मक प्रावधानों के चलते संभव हो सका।

इसके अलावा, दक्षिणी राज्यों की चिंता का बड़ा कारण जल्द ही होने वाला लोकसभा सीटों का वृद्धि होगी, जिससे उन्हें संसद में बड़ी आवाज मिलेगी। इसके अलावा यदि संसद की सीटें बढ़ाने का फैसला होता है तो भी उत्तरी राज्यों को ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि दक्षिण में जनसंख्या अनुपात के हिसाब से कम सीटें आएंगी। इसलिए भले ही

उत्तर-दक्षिण की सियासी प्रतिस्पर्धा में जनसंख्या वृद्धि जैसा नेक विचार सामने आया है। वहीं, जब जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, तब सीमा विस्तार का विचार भी नेताओं के मन में देर-संवर आया होगा। यह स्थिति वैश्विक हिंदुत्व के अनुकूल होगी।

जहां तक मुख्यमंत्रियों के बयान की बात है तो आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने तो यहां तक कह दिया है कि दो से ज्यादा बच्चे वाला व्यक्ति ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पायेगा। वहीं, पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी ऐसा कानून लाने की मांग हो रही है ताकि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें। वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकसभा परिसीमन प्रक्रिया से कई दंपतियों के ‘‘16 (तर्ह की संपत्ति) बच्चों’’ की तमिल कहावत की ओर वापस लौटने की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री ने जनगणना और लोकसभा परिसीमन प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि नवविवाहित जोड़ों अब कम बच्चे पैदा करने का विचार त्याग सकते हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों को 16 बच्चों का नहीं बल्कि 16 तरह की संपत्ति अर्जित करने और खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देते थे, जिसमें प्रसिद्धि, शिक्षा, वंश, धन आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि अब उन्हें सचमुच 16 बच्चे पैदा करने चाहिए, न कि एक छोटा और खुशहाल परिवार रखना चाहिए।

इस दिशा में हमारे बड़े-बड़े मंदिरों को भी सामने आना चाहिए और छोटे-छोटे मंदिरों का अकूत आय को साधक पूरी दुनिया में मंदिरों का जाल बिछाने और वहां हिंदुओं की आबादी बढ़ाने की निजी पंचवर्षीय योजना बनानी चाहिए। इसमें एनआरआई, भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों, विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लेना चाहिए। इससे हिंदुओं की आबादी और कारोबार दोनों में इजाफा होगा, यदि नेक मन से इसपर विचार किया जाए तो। इस नजरिए से भी उत्तर भारत के नेताओं को सोचना होगा। कहा भी गया है कि अग्र सोची, सदा सुखी।

- :सौजन्य :-

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

दिल्ली में तीन जगहों पर आयोजित होगा Auto Expo, कैसा रहेगा पूरा शेड्यूल

परिवहन विशेष न्यूज

भारत लगातार वाहन निर्माताओं के लिए बड़ा बाजार बनता जा रहा है। इसी को देखते हुए Bharat Mobility के पहले संस्करण के आयोजन के बाद दूसरी बार भी इसे आयोजित किया जा रहा है। January 2025 में होने वाले इस कार्यक्रम को कहाँ-कहाँ पर किया (Bharat Mobility 2025 Locations) जाएगा। कितनी कंपनियाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकती हैं।

नई दिल्ली। भारत में जिस तरह से वाहनों की मांग में बढ़ रही है उसे देखते हुए वाहन निर्माता

भी लगातार नई तकनीक और वाहनों को भारत में पेश कर रहे हैं। ऑटो एक्सपो की जगह अब Bharat Mobility के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। भारत मोबिलिटी के दूसरे संस्करण को कब और कहाँ आयोजित (When is Bharat Mobility Expo 2025) किया जाएगा। किस जगह पर किस तरह की तकनीक और वाहनों को देखा जा सकेगा। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

कब होगा आयोजन

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन अगले साल किया जाएगा। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि साल

2025 में इसका आयोजन 2024 के मुकाबले में ज्यादा बड़े स्तर पर किया जाएगा।

कहाँ होगा आयोजन

सरकार की ओर से भारत मोबिलिटी के दूसरे संस्करण के आयोजन के साथ ही वेन्यू की भी जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक अगले साल इस कार्यक्रम का आयोजन तीन स्थानों (Bharat Mobility 2025 Locations) पर होगा। जिसमें दिल्ली में भारत मंडपम, द्वारका में यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट शामिल हैं।

कहाँ लगेगा गाड़ियों का मेला

Bharat Mobility 2025 में मुख्य

कार्यक्रम दिल्ली के Bharat Mandapam में होगा। यहां पर 17 जनवरी से 22 जनवरी के बीच Auto Expo 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर इंडिया इंटरनेशनल टायर शो, इंडिया साइकिल शो, भारत बैटरी शो, स्टील पवेलियन और मोबिलिटी टेक पवेलियन का आयोजन किया जाएगा।

यशोभूमि में होगा कंपोनेंट शो का आयोजन

दिल्ली के द्वारका में भी Bharat Mobility 2025 का आयोजन किया जाएगा। यहां पर 18 जनवरी से 21 जनवरी के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिसमें कंपोनेंट शो को आयोजित

किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा में भी होगा कार्यक्रम

19 से 22 जनवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में भी इसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो और अर्बन मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर शो को आयोजित किया जाएगा।

कौन सी कंपनियाँ होंगी शामिल

ऑटो एक्सपो 2025 में कमर्शियल वाहन, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन, यात्री वाहन, विशेष वाहन, तीन पहिया, दो पहिया, मिलिटी वाहन, एग्रीकल्चरल वाहन को दिखाया जाएगा।

भारत ने भूटान के प्रधानमंत्री को हरित हाइड्रोजन बस दिखाई



परिवहन विशेष न्यूज

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगो और उनके प्रतिनिधिमंडल को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस दिखाई, जो हरित हाइड्रोजन गतिशीलता में भारत की बढ़ती प्रगति का प्रदर्शन है। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार इंडियन ऑयल द्वारा विकसित यह बस टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों को दर्शाती है।

इस कार्यक्रम में इंडियन ऑयल के अध्यक्ष और निदेशक (विपणन) वी सतीश कुमार सहित वरिष्ठ गणमान्य लोगों ने भाग लिया और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के एक प्रमुख घटक के रूप में हरित हाइड्रोजन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पुरी ने कहा कि हरित हाइड्रोजन में

भारत की प्रगति स्थायी ऊर्जा समाधानों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, "हम स्वच्छ, हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भूटान जैसे क्षेत्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक हैं।"

यह प्रदर्शन हरित ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए भारत और भूटान के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। भूटान के प्रतिनिधिमंडल ने अपने पर्यावरणीय स्थिरता प्रयासों के हिस्से के रूप में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को अपनाने में रुचि व्यक्त की।

इंडियनऑयल 2004 से हाइड्रोजन अनुसंधान में सबसे आगे रहा है, शुरुआत में हाइड्रोजन-सीएनजी मिश्रणों के साथ काम कर रहा था। हाल के वर्षों में, कंपनी ने अपनी हरित हाइड्रोजन पहलों का विस्तार

किया है, जिसमें हाइड्रोजन भंडारण, परिवहन और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों पर केंद्रित परियोजनाएं शामिल हैं। फरीदाबाद में इंडियनऑयल के आरएंडडी सेंटर में स्थित भारत का पहला हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन चालू है, और टाटा मोटर्स के साथ सहयोग से हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का विकास हुआ है।

वर्तमान में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भारतीय सेना और नौसेना के लिए एक-एक सहित आठ ईंधन सेल बसें चल रही हैं। वडोदरा में चार अतिरिक्त बसें चल रही हैं, जिन्हें इंडियनऑयल के हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। कंपनी के प्रयास पर्यावरण अनुकूल परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने में इसके नेतृत्व को मजबूत करते हैं।

हाइड्रोजन-ईंधन वाले परिवहन का यह प्रदर्शन भारत के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने और भविष्य के लिए एक व्यवहार्य ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन को विकसित करने की दिशा में व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल वाहनों में से एक माना जाता है, क्योंकि वे ग्रीन हाइड्रोजन पर चलते हैं, जो ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने पर केवल जल वाष्प और हाइड्रोजन को उपोत्पाद के रूप में उत्सर्जित करता है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण भारत ऊर्जा सप्ताह (IEW) के उद्घाटन समारोह के दौरान किया गया, जो 6 फरवरी को गोवा में शुरू हुआ था।

एक साल तक की वेंटिंग चल रही है। हालांकि गाड़ी के अलग-अलग वेरिएंट पर Waiting Period अलग हो सकता है। इसके डीजल वेरिएंट्स पर सिर्फ एक महीने की वेंटिंग चल रही है। लेकिन इसके पेट्रोल वेरिएंट्स पर एक महीने से लेकर एक साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

किस वेरिएंट पर सबसे ज़्यादा इंतजार

जानकारी के मुताबिक एसयूवी के पेट्रोल बेस वेरिएंट पर एक साल तक की वेंटिंग चल रही है। इसके बाद MX2, MX2 Pro और AX5 के लिए भी सात से आठ महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। IMX3 और MX3 Pro को खरीदना है तो आपको छह से सात महीने वेट करना होगा। एसयूवी के टॉप वेरिएंट्स AX5L, AX7 और AX7L को घर लाने के लिए आपको दो महीने का इंतजार करना होगा।

कितना दमदार इंजन

अपने सेगमेंट में आने वाली इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही 7.79 लाख रुपये है। इसका टॉप वेरिएंट कुल तीन इंजन के विकल्प देती है। जिनमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल से 83 किलोवाट की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दूसरे इंजन के विकल्प के तौर पर भी 1.2 लीटर की क्षमता का टीजीडीआई पेट्रोल इंजन मिलता है। जिससे 96 किलोवाट की पावर और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। वहीं तीसरे इंजन के तौर पर 1.5 लीटर की क्षमता का टर्बो डीजल इंजन मिलता है जिससे इसे 86 किलोवाट की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।

कितनी है कीमत

महिंद्रा की एकसयवी 3एक्सओ की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 7.79 लाख रुपये है। इसके टॉप वेरिएंट को 15.49 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है।

मर्सिडीज-बेंज ने यूरोप का पहला बैटरी रीसाइक्लिंग प्लांट खोला

परिवहन विशेष न्यूज

मर्सिडीज-बेंज ने यूरोप का पहला बैटरी रीसाइक्लिंग प्लांट खोला है जिसमें एक एकीकृत मैकेनिकल-हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रक्रिया है, जिससे यह दुनिया भर में अपनी खुद की इन-हाउस सुविधा के साथ बैटरी रीसाइक्लिंग लूप को बंद करने वाली पहली कार निर्माता बन गई है। दक्षिणी जर्मनी के कुपेन्हेम में रीसाइक्लिंग प्लांट एक वास्तविक सकुलर अर्थव्यवस्था बनाता है।

मौजूदा स्थापित प्रक्रियाओं के विपरीत, मैकेनिकल-हाइड्रोमेटलर्जिकल रीसाइक्लिंग प्लांट की अपेक्षित रिकवरी दर 96 प्रतिशत से अधिक है। लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे मूल्यवान और दुर्लभ कच्चे माल को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है - एक ऐसे तरीके से जो भविष्य के सभी इलेक्ट्रिक मर्सिडीज-बेंज वाहनों के लिए नई बैटरियों में उपयोग के लिए उपयुक्त है।

कंपनी ने नए बैटरी रीसाइक्लिंग प्लांट के निर्माण और इस प्रकार जर्मनी में मूल्य सृजन में करोड़ों यूरो का निवेश किया है। संघीय चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज और बाडेन-वुर्टेम्बर्ग के पर्यावरण मंत्री थेंक्ला वाकर ने बाडेन के कुपेन्हेम में उद्घाटन समारोह के लिए प्लांट का दौरा किया।

"मर्सिडीज-बेंज ने खुद को टिकाऊ तरीके से सबसे वांछनीय कारों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अग्रणी के रूप में यूरोप की पहली एकीकृत मैकेनिकल-हाइड्रोमेटलर्जिकल बैटरी रीसाइक्लिंग फैक्ट्री कच्चे माल की स्थिरता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उद्योग और विज्ञान के हमारे भागीदारों के साथ, हम जर्मनी और यूरोप में टिकाऊ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और मूल्यनिर्माण के लिए अभिनव ताकत का एक मजबूत संकेत भेज रहे हैं, र मर्सिडीज-बेंज ग्रुप एजी के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष ओला कर्लेनियस ने कहा।

"ऑटोमोबाइल का भविष्य इलेक्ट्रिक है और बैटरी इसका एक अनिवार्य घटक है। संसाधन-संरक्षण और संभारणीय तरीके से

परिवहन विशेष न्यूज

भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में उभरती हुई कंपनी क्वांटम एनर्जी ने अपने कुछ लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल पर दिवाली पर विशेष छूट की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमित समय के लिए यह ऑफर 18 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। यह छूट क्वांटम एनर्जी के सभी शोरूम में उपलब्ध है, जिसमें आगरा, लखनऊ और कानपुर में इसके नए खुले आउटलेट भी शामिल हैं।

यह ऑफर तीन मॉडलों पर लागू है प्लाज्मा एक्स, प्लाज्मा एक्सआर और मिलान। ग्राहक अब त्योहारी सीजन के दौरान इन स्कूटरों को कम कीमत पर खरीद सकते हैं। प्लाज्मा एक्स की कीमत ₹1,29,150 से घटकर ₹99,999 हो जाएगी; प्लाज्मा एक्सआर की कीमत ₹1,09,999 से घटकर ₹89,095 हो जाएगी और मिलान की कीमत ₹85,999 से घटकर ₹79,999 हो जाएगी।

कंपनी ने कहा कि ये मॉडल भारतीय यात्रियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता के बीच संतुलन प्रदान करते हैं। प्लाज्मा एक्स और प्लाज्मा

एक्सआर 1500W मोटर द्वारा संचालित हैं, जिनकी अधिकतम गति क्रमशः 65 किमी/घंटा और 60 किमी/घंटा है। 1000W मोटर से लैस मिलान 60 किमी/घंटा की शीर्ष गति तक पहुँचता है। स्कूटर की रेंज भी काफी अच्छी है: प्लाज्मा एक्स के लिए एक बार चार्ज करने पर 120 किमी तक और प्लाज्मा एक्सआर और मिलान के लिए 100 किमी तक।

क्वांटम एनर्जी लिमिटेड की निदेशक चेतना चुक्कापल्ली ने कहा, "दिवाली उत्सव का समय है, और क्वांटम एनर्जी में हम अपने ग्राहकों को इन विशेष छूटों के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर स्विच करने का अवसर प्रदान करने के लिए उत्साहित हैं। हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रदर्शन, विश्वसनीयता और पर्यावरण-मित्रता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये त्योहारी ऑफर अधिक लोगों को हरित भविष्य अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।"

कुसालावा इंटरनेशनल की सहायक कंपनी क्वांटम एनर्जी, जो 1964 से प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के लिए इंजन घटकों का निर्माण कर रही है, ने 2022 में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रवेश



किया। कंपनी ने तब से 10,000 से अधिक इकाइयाँ बेची हैं और इसे भारत के शीर्ष 10 ईवी दोपहिया ब्रांडों में स्थान दिया गया है। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के अलावा, सभी क्वांटम एनर्जी शोरूम विक्री, सेवा

और स्पेयर पार्ट्स सहित सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करते हैं। ग्राहक कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट राइड शेड्यूल कर सकते हैं या भारत भर में किसी भी शोरूम पर जा सकते हैं।

कंपनी ने कहा कि ये ऑफर अधिक उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों को एक टिकाऊ विकल्प के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, खासकर त्योहारी सीजन के दौरान।

रैपिडो ने भारत भर में 10,000 स्वैपेबल पियाजियो ईवी तैनात करने के लिए इंडोफास्ट एनर्जी के साथ किया सहयोग



परिवहन विशेष न्यूज

रैपिडो ने भारत भर में स्वैपेबल बैटरी वाले 10,000 पियाजियो इलेक्ट्रिक वाहन तैनात करने के लिए इंडियन ऑयल और सन मोबिलिटी के बीच एक संयुक्त उद्यम इंडोफास्ट एनर्जी के साथ सहयोग की घोषणा की है।

इस परियोजना के हिस्से के रूप में इंडोफास्ट एनर्जी ने दिसंबर 2024 के अंत तक हैदराबाद में 100 से अधिक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और बेंगलुरु में 200 से अधिक स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। रैपिडो का लक्ष्य इन स्वैपेबल इलेक्ट्रिक ऑटो को अपने बेड़े में शामिल

करना है ताकि टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा दिया जा सके और अपने दैनिक सवारी संचालन के एक हिस्से का समर्थन किया जा सके।

पियाजियो के ई-सिटी मैक्स इलेक्ट्रिक ऑटो, सन मोबिलिटी की बैटरी स्वैपिंग तकनीक के साथ एकीकृत, विस्तारित रेंज

और कम डाउनटाइम का लाभ प्रदान करते हैं। इस सहयोग से 2024 के अंत तक हैदराबाद, बेंगलुरु और अन्य प्रमुख शहरों से शुरू होकर पूरे दक्षिण भारत में 1,000 से अधिक ईवी शुरू होने की उम्मीद है।

साझेदारी को पहली बार 2023 में

बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की दक्षता और सुविधा में सुधार करने के लिए इंडोफास्ट एनर्जी की स्वैपेबल बैटरी तकनीक को रैपिडो के प्लेटफॉर्म में एकीकृत करना था।

दीवाली से पहले सोने और चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, चेक करें लेटेस्ट प्राइस

परिवहन विशेष न्यूज

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी आई। दोनों ने अपना नया ऑल-टाइम हाई बनाया है। चांदी का भाव लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में 1 लाख के पार रहा। त्योहारी और शादी-ब्याह के मौसम की मांग के चलते सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। एक्सपर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में भी सोने-चांदी की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है।

नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला बरकरार रहा है। दोनों कीमतों धातुओं का भाव लगातार छठे कारोबारी सत्र बढ़ा है। सोने की कीमत 500 रुपये बढ़कर 81,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं, चांदी 1,000 रुपये बढ़कर 1.02 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

चांदी का भी यह अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। पिछले छह कारोबारी सत्रों में चांदी का भाव 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गया है। वहीं, 16 अक्टूबर से सोने में 2,850 रुपये प्रति 10 ग्राम

की तेजी आई है।

क्यों बढ़ रहा सोने-चांदी का भाव

अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, त्योहारी और शादी-ब्याह के मौसम की मांग के चलते सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। इसकेआई कैपिटल के एमडी नरिंदर वाधवा के मुताबिक, फिजिकल मार्केट और एमसीएक्स पर चांदी के 1 लाख रुपये तक पहुंचने कई कारण हैं। इनमें भारत में सीजनल डिमांड और पश्चिम एशिया संघर्ष से भू-राजनीतिक जोखिम जैसे चीजें शामिल हैं।

सरकार ने जुलाई में, सोने और अन्य धातुओं पर मूल सीमा शुल्क में कटौती की थी। उसके बाद स्थानीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में 7 प्रतिशत की तेज गिरावट आई थी। हालांकि, मौजूदा फेस्टिव सीजन, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने जैसे फैक्टर ने सोने और चांदी की कीमतों को दोबारा हवा दी है।

क्या है एक्सपर्ट की राय

एलकेपी सिन्कोरिटीज में कर्मोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, रफिनाहाल, ब्याज दर का चक्र सोने में तेजी की सबसे बड़ी वजह है। साथ ही, आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों को लेकर अनिश्चितता भी सोने की कीमतों को ऊंचा रखने में भूमिका निभा रही है।

एचडीएफसी सिन्कोरिटीज में कर्मोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सोमिल गांधी ने कहा, रनिवेशक अस्थिरता के माहौल में गोल्ड का रुख कर रहे हैं। वहीं, मध्य पूर्व में तनाव के और बढ़ने की आशंका भी व्यापारियों को सोने की ओर खींच रही है। इससे

सोने के भाव में तेजी आ रही है। र मेहता इक्विटीज लिमिटेड में कर्मोडिटीज के उपाध्यक्ष राहुल कलंत्री ने कहा, रसोने और चांदी ने काफी मजबूत प्रदर्शन किया है। सोने की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जबकि चांदी 35 अमेरिकी

डॉलर प्रति औंस पर 12 साल के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है।' हालांकि, एशियाई बाजार में चांदी 0.86 प्रतिशत गिरकर 34.74 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर बेली गई। दिन के दौरान इसने 35.055 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस का नया शिखर छुआ।

जन धन योजना से जन-निवेश : क्या भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बदलाव

आज म्यूचुअल फंड के निवेशकों की संख्या में शानदार तेजी देखने को मिली है। निवेशक धड़ाधड़ इसमें निवेश कर रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जन-धन योजना से बैंकिंग सिस्टम को लाभ हुआ। वहीं दूसरी तरफ यह योजना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए चुनौती बन गया। ऐसे में सवाल है कि क्या अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बदलाव की जरूरत है?

नई दिल्ली। साल 1995 में, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया (भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन) बनाने के लिए कुछ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स (एमएफ) के चीफ एजीक्यूटिव ऑफिसर एक साथ आए।

यह एसोसिएशन बनाने के पीछे उद्देश्य उन निवेशकों को आकर्षित करने का था , जिनकी सोच प्रॉपर्टी, गोल्ड या बैंक डिपॉजिट से आगे नहीं बढ़ पाती थी या इससे अलग उन्होंने कुछ नहीं नहीं देखा था। हालांकि, इसके बाद भी कई दशकों तक म्यूचुअल फंड के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, भारतीय निवेशकों ने इसे काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया।

साल 2014 तक, म्यूचुअल फंड (एमएफ) भारतीय परिवारों के फाइनेंशियल एसेट्स का 5 फीसदी से भी कम प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन साल 2024 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए स्थिति पूरी तरह बदल गई है। आरबीआई गवर्नर सहित कई लोगों ने हाल ही में म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के बारे में चिंता जताई है, जिनमें भारी संख्या में भारतीय निवेशक पैसा लगा रहे हैं, जिससे बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ सुस्त पड़ गई है। पिछले दशक में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 6 गुना बढ़ गई है और अब यह बैंक डिपॉजिट के 30 फीसदी के बराबर है।

आखिर इस ग्रोथ को किसने संचालित किया है ? जबकि पिछली पीढ़ी के निवेशकों ने मुख्य रूप से अपनी जमा पूंजी को पूरी तरह से सुरक्षित रखने पर फोकस किया था और पीपीएफ और बैंक डिपॉजिट जैसे कन्जर्वेटिव कहे जाने वाले निवेश के विकल्पों को चुना था, वहीं आज का युवा अपने निवेश पर अधिक रिटर्न चाहता है। भारत में, निवेशक अब अपनी लाइफ स्टाइल को फाइनेंस करने और अपने जीवन के तमाम लक्ष्य को पूरा करने में मदद के लिए अपनी बचत में 'कुछ ज्यादा' की तलाश कर रहे हैं।

पिछले 2 दशक में, ज्यादातर इक्विटी फंड ने निवेशकों की संपत्ति में 15-20 गुना बढ़ोतरी की है, जो कि बैंक डिपॉजिट जैसे पारंपरिक निवेश के विकल्प में हासिल किए गए रिटर्न की गई तुलना में लगभग 4-5 गुना अधिक है। निवेशकों के लिए जागरूकता अभियान र म्यूचुअल फंड सही हैर के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया गया कि अधिक से अधिक निवेशक इस नए एसेट क्लास के बारे में समझें और इसे लेकर जागरूक हो जाएं, जिसे उन्होंने लंबे समय तक नजरअंदाज कर दिया था।

हालांकि, म्यूचुअल फंड अब तक सिर्फ 5 करोड़ निवेशकों तक ही पहुंच पाए हैं, यानी इसकी पहुंच आबादी के करीब 3 फीसदी लोगों तक ही है। अब तक 10 में से एक भी बैंक अकाउंट होल्डर ने म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में निवेश नहीं किया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) का दो तिहाई हिस्सा टॉप 15 शहरों से आता है, जो यह संकेत देता है कि अभी म्यूचुअल फंड की पहुंच बहुत कम क्षेत्रों व लोगों तक है। इंडस्ट्री की शुरुआत तो मजबूत हुई है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

केंद्र सरकार ने भारत ब्रॉड के तहत सस्ते दाम में साबुत चना और मसूर दालबेचने का फैसला किया है। इससे उम्मीद है कि दालों की कीमतों में नरमी आएगी और त्योहारी सीजन में आम जनता को राहत मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और केन्द्रीय भंडार के जरिये साबुत चना 58 रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा।

नई दिल्ली। पिछले कई महीनों से जनता महंगाई की मार से परेशान है। खासकर, खाद्य महंगाई ने उसके रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। आलू, टमाटर और प्याज के साथ दालों के भाव भी काफी बढ़ गए हैं। अब सरकार ने त्योहारी सीजन में महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए 'भारत' ब्रॉड के तहत साबुत चना और मसूर दाल भी बेचने का फैसला किया है। वह दिल्ली-एनसीसी और जैसी जगहों पर रियायती दामों पर पहले ही प्याज बेच रही है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को सब्सिडी वाली दालों के अपने कार्यक्रम के विस्तार का एलान किया। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी का कहना है कि सहकारी नेटवर्क भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड

किलोग्राम (29 रुपये से अधिक), चना दाल के लिए 70 रुपये प्रति किलोग्राम (60 रुपये से ऊपर) हैं।

वहीं मूंग दाल तथा मूंग साबुत की कीमत क्रमशः 107 रुपये प्रति किलोग्राम और 93 रुपये प्रति किलोग्राम है। सरकार प्याज के लिए 35 रुपये प्रति किलोग्राम और टमाटर के लिए 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर बनाए रखने की भी कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने इस वर्ष दालों के बेहतर उत्पादन की उम्मीद जताई है क्योंकि सरकार ने दालों के समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि की है।

सस्ती प्याज भी बेच रही सरकार

सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए

(नेफेड) और केन्द्रीय भंडार के जरिये साबुत चना 58 रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा।

दालों का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद

सरकार ने सहकारी समितियों को तीन लाख टन चना और 68,000 टन मूंग आवंटित किया है। एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक अनीस जोसेफ चंद्रा ने कहा कि वितरण दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू होगा। 10 दिन के भीतर इसके देशव्यापी विस्तार की योजना है। प्रथम नेटवर्क भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड

इस फेस्टिव सीजन सोने-चांदी के अलावा ये शानदार ऑप्शन भी मौजूद, आपके लिए कौन-सा रहेगा बेहतर ?

परिवहन विशेष न्यूज

फेस्टिवल सीजन में ज्वेलरी की डिमांड बढ़ जाती है। अब गोल्ड और सिल्वर के अलावा अब रोज गोल्ड और व्हाइट गोल्ड भी अच्छा ऑप्शन हो गया है। वैसे तो यह गोल्ड से महंगा होता है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि व्हाइट गोल्ड और रोज गोल्ड में क्या अंतर है और आपके लिए कौन-सा बेहतर ऑप्शन रहेगा।

नई दिल्ली। फेस्टिवल सीजन में ज्वेलरी खरीदना लोगों को पसंद आती है। दरअसल, भारत में ज्वेलरी की खरीदारी काफी शुभ मानी जाती है। इसके अलावा महिलाओं को ज्वेलरी की शॉपिंग करना काफी पसंद है। ज्वेलरी शॉपिंग की बात आती है तो हमारे ध्यान में गोल्ड, सिल्वर और डायमंड आता है। इसके अलावा भी अब दो मेटल काफी पॉपुलर हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं व्हाइट गोल्ड (White Gold) और रोज गोल्ड (Rose Gold) की। इन दोनों गोल्ड को काफी



लंग्जरी, एस्थेटिक माना जाता है। कई लोग इन दोनों गोल्ड को लेकर काफी कन्फ्यूज होते हैं। हम आपको इन दोनों के अंतर के साथ बताएंगे कि आपके लिए कौन-सा बेहतर ऑप्शन रहने वाला है।

सामान्य गोल्ड से कितने अलग हैं दोनों गोल्ड के कई भी कई प्रकार होते हैं। जो सामान्य सुनार के पास गोल्ड मिलता है वो प्योर

अलग होते हैं। यह सामान्य सुनार की दुकान पर उपलब्ध नहीं होता है। इसकी वजह है कि यह काफी लंग्जरी और एस्थेटिक होता है। कई लोग इसकी सादगी और रंग की वजह से पसंद करते हैं तो वहीं कई इसकी कीमत की वजह से इसे पसंद करते हैं। अगर आप भी इन दोनों में से कुछ खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको एक बार देख लेना चाहिए कि आपके लिए इनमें से कौन-सा बेहतर है।

रोज गोल्ड क्या होता है

रोज गोल्ड के नाम से ही समझ आता है कि इसका रंग गुलाब जैसे हल्का पंक होगा। इसमें 75 फीसदी शुद्ध सोना होता है। इस गोल्ड में जो गुलाबी रंग आता है वह गोल्ड के साथ कॉपर और सिल्वर की मिलावट करने की वजह से आता है। जब गोल्ड में कॉपर मिलाया जाता है तो यह एक तरह से गुलाबी रंग का इफेक्ट देता है। इसके अलावा यह ज्वेलरी को डिजाइन करने में भी मदद करता है। अगर इसमें ज्यादा कॉपर मिला दिया जाए तो गोल्ड का रंग डार्क पंक हो जाएगा।

है महंगा

व्हाइट गोल्ड और रोज गोल्ड के रंग के साथ ही इसकी कीमत में भी काफी अंतर है। हालांकि, इन दोनों के दाम इनके कारेटेज (Caratage) पर निर्भर करता है। इन दोनों गोल्ड के दाम इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों में कौन-से मेटल को मिलाया गया है। रोज गोल्ड में कॉपर मिलाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत व्हाइट गोल्ड की तुलना में काफी कम रहती है। इसके बावजूद एक्सपर्ट रोज गोल्ड की जगह व्हाइट गोल्ड को काफी अच्छा ऑप्शन मानते हैं।

कौन-सा है बेहतर ऑप्शन

अब ऐसे में सवाल आता है कि इन दोनों में से आपके लिए कौन-सा बेहतर ऑप्शन है। इन दोनों की प्रॉपर्टी काफी अलग है। ऐसे में आपको सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इसे खरीदना चाहिए। हमन आपको ऊपर इमेज में रोज गोल्ड और व्हाइट गोल्ड के फैक्टर्स के बारे में बताया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद ही इसे खरीदें।

लगातार तीसरे दिन गिरा बाजार, सेंसेक्स 158 अंक लुढ़कर हुआ बंद

शेयर बाजार के दोनों सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में बाजार हल्की बढ़त के साथ खुला था। विदेशी निवेशकों द्वारा हो रही निकासी और ऑटो-फार्मा में हो रहे मुनाफावसूली के कारण भी बाजार में गिरावट आई। आज बजाज फाइनेंस के शेयर बाजार के टॉप गेनर रहे। आइए आज के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार की चाल पर नजर डालते हैं।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज लगातार तीसरे दिन मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ। विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के बीच ऑटो, फार्मा और कैपिटल गूड्स के शेयरों में मुनाफावसूली के कारण आज बाजार में गिरावट आई।

उतार-चढ़ाव भरे सत्र में सेंसेक्स 138.74 अंक या 0.17 फीसदी की गिरावट के साथ 80,081.98 अंक पर बंद हुआ। आज इंट्रा-डे में सेंसेक्स 80,000 अंक से नीचे गिरकर 79,891.68 के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई निफ्टी 36.60 अंक या 0.15 फीसदी गिरकर 24,435.50 अंक पर बंद हुआ।

आज के टॉप गेनर और लूजर स्टॉक

आज सेंसेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, लार्सन एंड टुब्रो, आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। बजाज फाइनेंस के शेयर आज के टॉप गेनर रहे। इनके साथ टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और बजाज फिंसर्व के शेयर भी के साथ

कारोबार कर रहे हैं।

धोमी कमाई और एफआईआई की तीखी प्रतिक्रिया से निवेशकों की मानसिकता निराशाजनक हो गई, जिससे बाजार की धारणा प्रभावित हुई। हालांकि, हालिया गिरावट के बाद मिड और स्मॉल-कैप सौदेबाजी का अनुभव कर रहे हैं, हालांकि इस गति-संचालित खरीदारी की स्थिरता अनिश्चित बनी हुई है अमेरिका में 10-वर्षीय उपज में वृद्धि हुई है, जो फेड द्वारा दर में कटौती की धोमी गति का संकेत है, जो उभरते बाजारों के प्रति जोखिम-मुक्त भावना के लिए तैयार है।

एशियाई बाजारों में, सियाल, शंघाई और हांगकांग ऊंचे स्तर पर बंद हुए जबकि टोक्यो निचले स्तर पर बंद हुआ। यूरोपीय बाजार मिश्रित रुख पर कारोबार कर रहे थे। मंगलवार को अमेरिकी बाजार सपाट बंद हुए। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेट क्रूड 0.97

प्रतिशत गिरकर 75.30 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 3,978.61 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,869.06 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी।

सपाट बंद हुआ रुपया

आज के कारोबारी सत्र में रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय करेंसी ग्रीनबैंक के मुकाबले 84.07 पर खुली और पूरे सत्र में एक सीमित दायरे में कारोबार किया। अंततः डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले सत्र के समापन स्तर 84.08 (अंतिम) पर बंद हुई। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की गिरावट के साथ 84.08 पर बंद हुआ था।



